आई.एस.एस.एन. संख्या : 2454–2458
नवरचना NAVRACHNA
www.grefiglobal.org/journals/navrachna.2024
वर्ष 10 अंक 1–2, जून–दिसम्बर 2024, पृ. 41–50

स्वयं सहायता समूहः ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन का नवीन आयाम

अनुपमा यादव*
सत्या मिश्रा**

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण समुदाय में स्वयं सहायता समूह को परिवर्तन के एक नवीन आयाम के रूप में विश्लेषित करने का प्रयास करता है; क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों को अपने कामकाज और व्यवसाय के लिए ऐसे ऋण की आवश्यकता होती है जो उन्हें समय पर उपलब्ध हो जाए और जिसे आसान किस्तों में वापस लौटाया जा सके। औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था इन आवश्यकताओं का उचित तरीके से समाधान नहीं कर पातीं और ऋण के अनौपचारिक स्रोत, जैसे महाजन, उच्च ब्याज दर पर इनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए ग्रामीणों की साझी बचत के माध्यम से बचत एवं ऋण समूहों की आवश्यकता अनुभव होती है जो उनके लिए उधार पाने का स्रोत साबित हो सके। इस प्रकार 'स्वयं सहायता समूह' एक ऐसा सामूहिक संगठन है, जिसमें व्यक्तिगत परेशानियों से जूझ रहे व्यक्ति, कमजोर महिलाएं या समाज के निम्न वर्ग के व्यक्ति शामिल होते हैं। ये समूह मूल रूप से ग्रामीण समाज में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बनाए जाते हैं। जैसा कि फ्रांसीसी दार्शनिक, बौद्धिक और सामाजिक विचारक 'सिमोन डी बुआ' ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक "द सेकेंड सेक्स 1949" में कहा है कि 'औरत जन्म से औरत नहीं होती, बल्कि बाद में वह औरत हो जाती है।' अर्थात् महिलाओं की स्थिति उसके चरित्र का एक परिणाम नहीं है, बल्कि महिला का चरित्र उसकी स्थिति का परिणाम है। जहां महिलाओं की स्थिति का निर्धारण आर्थिक सशक्तिकरण से होता है। बैंक से सम्बद्ध होने के कारण स्वयं सहायता समूह ग्रामीण जनता को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने एवं छोटे मोटे व्यवसाय स्थापित करने में सहायता करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (NRLM), एवं 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के माध्यम से सरकार भी ग्रामीण समुदाय के लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मुख्य शब्दः स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण समुदाय, परिवर्तन, NRLM, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

---

*शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, anupama300788@gmail.com
**प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, नारी शिक्षा निकेतन पी0जी0 कालेज, लखनऊ

ग्रामीण जीवन को समझने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विशेष तौर पर भारत जैसे अधिसंख्य ग्रामीण जनसंख्या वाले देश में ग्रामीण समाजशास्त्र की ग्राम्य अध्ययनों में भूमिका के संदर्भ में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं; प्रथम, कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ग्रामीण जीवन के विकास के नियमों को ढूंढ निकालने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की भांति एक विज्ञान है। इसलिए इसे ग्रामीण सामाजिक जीवन की समस्याओं का अध्ययन करने, अनुसंधान करने एवं सिद्धांत निर्माण करने तक ही सीमित रहना चाहिए। वास्तव में ग्रामीण समाजशास्त्री न तो प्रशासक हैं और न ही योजना निर्माण करने वाले। अतः व्यावहारिक उपयोग ग्रामीण समाजशास्त्र के कार्य क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। द्वितीय, कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने वाले तो अन्य कई विज्ञान हैं। अतः इस विज्ञान का उपयोग ग्रामीण जीवन की समस्याओं को हल करने तथा पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता प्रदान करके ग्रामीण समाजशास्त्र को एक व्यावहारिक विज्ञान होने का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। एक तीसरा मत भी है जो समन्वयात्मक है–

कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करे तथा प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग ग्रामीण समस्याओं को हल करने में करे। इस संबंध में गिलिन कहते हैं, "हम ग्रामीण समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की वह शाखा मान सकते हैं जो ग्रामीण समुदायों का उनकी दशाओं एवं प्रवृत्तियों का अन्वेषण कर एवं प्रगति के सिद्धांत निर्माण का व्यवस्थित अध्ययन करती है।" इस प्रकार आज जरूरत है ऐसी सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जो सर्व समावेशी हो, व्यावहारिक हों, कार्यान्वयन में आसान हों और इसके लिए सरकार के साथ–साथ अन्य सभी हितधारकों को मिलकर नवोन्मेषी सोच लेकर चलने की आवश्यकता है। तत्पश्चात् ग्रामीण समाज एवं देश का समग्र व सतत विकास सुनिश्चित हो पाएगा। जिसके लिए आवश्यक है समान सोच, समान भाव और समान संरक्षण, जो समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह सभी संभावनाएं तभी सार्थक हो सकती हैं जब समानता के साथ–साथ आर्थिक सशक्तिकरण की बात भी की जाए। जिसके लिए बांग्लादेश में 1970 के दशक के दौरान गरीब और समाज के निम्न तबके के लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु 'स्वयं सहायता समूह' की अवधारणा को 'बांग्लादेश ग्रामीण बैंक' द्वारा प्रारम्भ किया गया था। जिसके कारण इसके संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नोबल पुरस्कार दिया गया था।

विकासशील देशों के लिए 'स्वयं सहायता समूह' जमीनी स्तर पर जन सामान्य के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम है। वहीं दूसरी ओर इस अवधारणा को न केवल

सामान्य लोगों द्वारा अपनाया जाता है अपितु दुनिया भर की सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाएं भी 'स्वयं सहायता समूह' के महत्व को भली–भाँति समझती हैं।

भारत में अनौपचारिक समूहों के रूप में कार्य करने की शुरुआत 1954 ई. में 'अहमदाबाद मजदूर संघ' ने की। जिसमें मिल मजदूरों के परिवार की महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे कौशल सिखाने के लिए संगठन बनाए गए। तत्पश्चात् 'इला भट्ट' ने 1972 ई. में स्व–रोजगार महिला संगठन (SEWA) की स्थापना की। जिसका उद्देश्य फेरीवालों, बुनकरों, कुम्हारों और असंगठित क्षेत्र की अन्य गरीब महिलाओं की आय को बढ़ाना था। परंतु भारत में आर्थिक उदारीकरण (1991–1992) के दौरान स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया तथा इस प्रक्रिया में 'नाबार्ड' की भूमिका प्रमुख रही। वहीं भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के दौरान 'स्वयं सहायता समूह' को जमीनी स्तर पर विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में उपयोग में लाया गया।

यदि बात ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हो तो वह मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है। ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जिसके कारण भारतीय समाज में ग्रामीण पिछड़ी हुई दशा में जीवन व्यतीत करते हैं। प्रशासन एवं गैर–सरकारी संगठनों के द्वारा ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु अनेक प्रयत्न किए गए हैं। ग्रामीणों में लघु वित्त के माध्यम से अनेक प्रकार के व्यवसाय संचालित किए जा रहे हैं। अतः ग्रामीणों में स्वावलंबन की स्थिति निर्मित हुई है। विभिन्न बैंक लिंकेज कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें आर्थिक मदद आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके फलस्वरुप ग्रामीण उद्यमिता एवं सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। अतः इस दृष्टि से यह जानना आवश्यक है कि स्वयं सहायता समूहों (लघु वित्त) के कारण ग्रामीण उद्यमियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। इस हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैः–

अध्ययन के उद्देश्य

1. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण आपूर्ति का अध्ययन करना।
2. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्पन्न महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण तथा परिवारों की सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण समाज की परंपरागत आर्थिक संरचना में आ रहे परिवर्तनों को पहचानना।

भारतीय समाजशास्त्र के अन्तर्गत ग्रामीण समाजशास्त्रीय अध्ययनों की परम्परा स्वतंत्रता के पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह की अवधारणा 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अर्थिक सुधारों के साथ सामने आई। इसके परिणामस्वरूप कुछ समय पश्चात् इससे सम्बन्धित साहित्य उसके बाद से प्राप्त होता है। अतः स्वयं सहायता समूह ग्रामीण जीवन में किस प्रकार के परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं, इसका अध्ययन भी

अत्यंत नया है। प्रस्तुत अध्ययन में उपर्युक्त उद्देश्यों को जानने के लिए साहित्य सर्वेक्षण इस प्रकार हैं:–

शशि पाण्डेय ने 'स्वयं सहायता समूह, लघु ऋण एवं महिला सशक्तिकरण का एक अध्ययन' में कहा है कि स्वयं सहायता समूहों को लघु ऋण प्रदान करने से ग्रामीण महिलाओं की भौतिक गतिशीलता, निर्णय के अधिकारों में वृद्धि, सौदा, शक्ति तथा विभिन्न स्तरों पर समस्या समाधान करने की शक्ति में वृद्धि होने के कारण ग्रामीण विकास प्रक्रिया में उनका योगदान उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उनके विकास के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के इस प्रयास की सार्थकता भी सामने आ रही है कि गांव की महिलाएं घर से बाहर निकल कर बैंक, ब्लॉक, अस्पताल तथा बाजार के कार्यों को स्वयं कर रही हैं और विभिन्न व्यवसाय को कुशलतापूर्वक सम्पादित कर यह सिद्ध कर चुकी हैं कि मात्र वे घर के कार्यों में ही नहीं बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को करने में कुशल एवं निपुण हैं (पाण्डेय शशि, 2016)।

स्टुअर्ट रदरफोर्ड (1997) ने हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द पुअर एंड देयर मनी' में कई प्रकार की जरूरत का जिक्र किया है: जीवन चक्र की जरूरतः शादी–विवाह, अंत्येष्टि, बच्चे का जन्म, शिक्षा, घर बनाना, विधवापन, बुढ़ापा इत्यादि; व्यैक्तिक आपात स्थितिः बीमारी, घायल होना, बेरोजगारी, परेशानी अथवा मृत्यु; तथा विपदाएंः आग, बाढ़, चक्रवात और मानव निर्मित घटनाएं जैसे–युद्ध।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गीकृत करने योग्य ऐसी बहुत गतिविधियां हैं जिनका मुद्रीकरण नहीं किया जाता है, अर्थात ऐसी गतिविधियां चलाने के लिए धन का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर परिभाषित करें तो गरीब लोगों के पास बहुत कम पैसा होता है। लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं जिनसे निपटने के लिए इनको धन की या वस्तु खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है।

वंदना शिवा (1999) ने अपनी पुस्तक 'कॉलोनियलिज्म एंड द इवोल्यूशन ऑफ मस्कुलनिस्ट फॉरेस्ट्री' में कहा है कि महिलाओं में पृथ्वी के समान ही उत्पन्न करने की सृजनात्मक शक्ति होती है। वह अपनी कल्याणकारी शक्तियों का उपयोग करके विभिन्न पर्यावरणीय पोषणकारी संसाधनों, नीतियों और प्राकृतिक तरीकों का ज्ञान सहज ही प्राप्त कर लेती है। जो कि शत प्रतिशत सत्य भी है। क्योंकि महिलाएं जिस हिम्मत और साहस के साथ घर, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को निर्वहन करती हैं, वह पुरुष के लिए संभव नहीं है। फिर भी महिलाएं स्वयं को पुरुषों की भीड़ में पीछे खड़ा पाती हैं। क्योंकि वे घर की चारदीवारी की जिम्मेदारियों को छोड़ कर बाहर नहीं निकल पाती हैं।

दीनदयाल अंत्योदय मिशन (DAY NRLM) के तहत महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। यह मिशन 28 राज्यों व 5 UTs के 600 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 45 लाख स्वयं सहायता समूहों की मदद से पांच करोड़ महिलाओं को संगठित किया जा चुका है (कुरुक्षेत्र अप्रैल 2024)। बाली स्वाइन व वर्गीस (2014) के अनुसार 'स्वयं सहायता समूहों' के माध्यम से महिलाओं में कौशल उन्नयन होता है। उन्हें विभिन्न स्वरोजगारी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अलका श्रीवास्तव (2005; 2006) द्वारा 'स्वयं सहायता समूहों' की महिला उद्यमिता एवं सशक्तिकरण में भूमिका का अध्ययन करने पर पाया गया कि 'स्वयं सहायता समूह' की महिलाओं के आत्मविश्वास एवं सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई है। स्वाइन एवं वेलेंटाइन (2007) आदि के अध्ययनों से ज्ञात होता है कि समूह से जुड़ने के पश्चात् पारिवारिक बचत में वृद्धि होती है। हाशमी एवं रिले (1996), कबीर (1998), त्रिपाठी (2010) आदि ने अपने अध्ययन में पाया कि 'स्वयं सहायता समूह' का सदस्य बनने के पश्चात् परिवार में प्रमुख मामलों में महिलाओं की आवाज सुनी जाने लगी है।

रोहित गुप्ता एवं आशीष पांडे ने 'आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (अमूल)' एक सफल उद्यम का उल्लेख करते हुए कहा है कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण उद्यमिता के एक अनूठे रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां एक समुदाय के भीतर व्यक्ति एक सामूहिक इकाई बनाने के लिए एक साथ आते हैं। यह समूह आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने और आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने संसाधनों, कौशल और प्रतिभाओं को एकत्रित करते हैं। स्वयं सहायता समूह अक्सर हस्तशिल्प, लघु स्तरीय कृषि और सूक्ष्म उद्यमों जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वयं सहायता समूह से उभरने वाले स्टार्टअप्स जिम्मेदारी की साझा भावना और सामुदायिक विकास पर ध्यान देने के साथ सहयोगी प्रकृति के हो सकते हैं। पूरे समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठाने के लिए समूह के अंतर्गत व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर जोर दिया जाता है (कुरुक्षेत्र, जनवरी 2024)।

महिला सशक्तिकरण के विषय में नकवी, हिना (2023) ने 'समता मूलक समाज का ताना–बाना' नामक शीर्षक के अंतर्गत कहा है कि "वर्तमान ही नहीं, भविष्य के दृष्टिगत, अल्पकालिक ही नहीं, दीर्घकालिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं से उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। केंद्र सरकार की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं में मूल लाभार्थी के रूप में महिलाओं को रखा गया है। चाहे वह आवासीय योजना हो, रोजगार सृजन हो, या बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य की बात हो, महिलाओं को आगे रखने के पीछे अवधारणा यही है कि उन्हें आगे रखकर हम एक समावेशी और समतामूलक समाज का निर्माण कर सकते हैं (कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2024)।"

1999 में सेवा बैंक ने सफलतापूर्वक अपने 25 साल पूरे किए। सेवा का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को संगठित करना है जो संपूर्ण रूप से रोजगार और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रवृत्त है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'सेवा' ने भारत और विदेश में 1500 स्वयं–सेवा समूह, सहकारी समितियां और संघ बनाये हैं (पांडे, मृणाल. 2006 पृष्ठ.133)।

पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन के एक नवीन आयाम के रूप में 'स्वयं सहायता समूहों' का अध्ययन किया गया है। यहां नारीवादी दृष्टिकोण से महिलाओं के सशक्तिकरण को जानने की कोशिश की गई है। जिसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक पद्धति का उपयोग करने के साथ–साथ अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में प्राथमिक स्रोत से डेटा संग्रह किया गया जिसके लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच अनुसूची का प्रयोग किया गया तथा समूह के सदस्यों का गहन साक्षात्कार भी लिया गया। नमूना चयन के लिए उद्देश्यपूर्ण नमूना पद्धति अपनाते हुए कुल पंद्रह स्वयं सहायता समूहों जैसेः आरती, राधिका, पूजा, कृषि, श्री राधे, कर्म, दुर्गा, उत्कर्ष, बुद्ध प्रेरणा, रविदास नारी, गायत्री आदि से विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश की गई। इन स्वयं सहायता समूहों में लगभग 180 सदस्यों में से 124 सदस्यों का चुनाव किया गया। जिसके लिए फॉर्मूला $n = N/(1+N(e)^2$ प्रयोग में लिया गया है।

परिणाम एवं विश्लेषण

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि लखनऊ जनपद के बख्शी का तालाब प्रखण्ड स्थित गोहानाकलां गांव में कुल पंद्रह स्वयं सहायता समूह वर्तमान समय में सक्रिय हैं। जिसमें से सात समूह 2015 में निर्मित हुए हैं, शेष समूह बाद में गठित किए गए। समूह में सहभागी महिलाओं की संख्या लगभग 180 है। स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के पश्चात् महिलाओं में काम करने की ललक, बाहर निकलने की हिम्मत, धन के लेन–देन में सहूलियत और पारिवारिक सम्मान आदि में पहले से बेहतर स्थिति हुई है। महिलाओं के उत्तर से यह ज्ञात हुआ कि वे अब बैंक से जुड़े सभी कार्य स्वयं कर रही हैं और घर के महत्वपूर्ण कार्यों में ऋण लेकर उसे आसान किस्तों में वापस भी कर रही हैं, क्योंकि स्वयं सहायता समूह से ऋण लेने पर उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव की स्थिति समूह के अन्य सदस्यों से बेहतर स्थिति देखने को मिली। समूह में जुड़ने के उपरांत इन लोगों ने जमीन, जानवर और अन्य प्रकार की संपत्ति बना लीं, परन्तु कोई भी सदस्य ऐसी नहीं मिलीं जिन्होंने समूह में जुड़ने के उपरांत किसी प्रकार की संपत्ति निर्मित की हो। इसके

बावजूद भारत में हाल के वर्षों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने वाले नवोन्मेषी उद्यमों में उत्साह के चलते स्टार्टअप इकोसिस्टम में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। एक लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। परंपरागत रूप से शहरी केंद्रों में केंद्रित स्टार्टअप संस्कृति अब ग्रामीण इलाकों में प्रवेश कर रही है, जिससे नवाचार और आर्थिक परिवर्तन के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। जिसमें स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ग्रामीण उद्यमिता के एक अनूठे रूप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां एक समुदाय के अंतर्गत एक सामूहिक इकाई बनाने के लिए एक साथ आते हैं। प्रस्तुत शोध के दौरान ग्रामीण समुदाय में स्वयं सहायता समूह' से जुड़ी महिलाओं के तथ्य संकलन एवं विश्लेषण से पता चलता है कि गांव में लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। समूह में जुड़ने से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी परिलक्षित होते हैं।

चुनौतियां एवं सीमाएं

जहां महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए समर्पित सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसेः लैंगिक समता–उन्मुख योजनाएं, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि संचालित की जा रही हैं। जिसका लक्ष्य ग्रामीण समुदाय के प्रत्येक निर्धन परिवार से कम–से–कम एक महिला को 'स्वयं सहायता समूह' से जोड़कर और रोजगार के सतत् अवसर प्रदान कर उन्हें गरीबी के कुचक्र से बाहर निकालना है। वहीं गोहनाकलां गांव में आरती, राधिका, पूजा, कृषि, श्री राधे, दुर्गा, उत्कर्ष, बुद्ध, रविदास नारी,गायत्री और कर्म नामक स्वयं सहायता समूहों का अध्ययन करने के उपरान्त यह जानकारी हुई कि समूह के सदस्यों में कुछ नवीन करने की उत्सुकता नहीं है अपितु वे एक दूसरे को देख कर सदस्यता ली हुई हैं। यदि समूह का कोई सदस्य ऋण लेता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होती है जिसके लिए कुछ शर्तें अवश्य होनी चाहिए। समूह में प्रत्येक सदस्यों की स्थिति अलग–अलग है। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव की स्थिति तो अलग होती ही है, परंतु समूह के अन्य सदस्यों में भी अंतर देखने को मिला। शिक्षित महिलाएं ज्यादा सक्रिय एवं लाभान्वित हो रही हैं। वहीं कम शिक्षित या अशिक्षित महिलाएं इस अवसर का पर्याप्त फायदा नहीं उठा पा रही हैं।

निष्कर्ष

भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की प्रस्थिति काफी महत्वपूर्ण है। महिलाएं न केवल पारिवारिक कार्यों के साथ ही जुड़ी हुई हैं अपितु आर्थिक गतिविधियों में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। गांव में आज भी मुख्य व्यवसाय कृषि ही है और कृषि का कार्य बिना महिला के सहयोग से संभव नहीं है। इससे यह आशय निकलता है कि महिला के बिना न तो परिवार चल सकता है और न ही समाज। जितना महत्वपूर्ण स्थान समाज में पुरुष का है, उतना ही महिला का भी है। भारतीय गांव में महिलाओं की प्रस्थिति को जानने के लिए गोहनाकलां गांव में शोध कार्य किया और पाया कि साठ प्रतिशत महिलाएं वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए स्वयं सहायता समूह' से जुड़ी हैं। वित्तीय आत्मनिर्भरता ग्रामीण महिलाओं में सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं, निर्णय लेने में सक्षम बना रही है, पैसे को अपने तरीके से व्यय करने की आजादी मिल रही है और वित्तीय आत्मनिर्भरता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव उनके जीवन पर दिखाई देता है कि उन्हें किसी के सामने नीचा नहीं दिखाया जाता।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सदियों से महिलाएं चाहे घर पर हों या समकालीन समाज में, समुदायों और राज्यों में हों, वे अपनी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां बखूबी जानती भी हैं और निभाती भी हैं। बदलते समय के साथ जहां महिलाओं के लिए समाज नई चुनौतियां लेकर आया है, वहीं पुरुषों ने भी महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदली है। विकास के पथ पर अग्रसर महिलाएं सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं। भारत के राज्यों और पंचायतों में भी महिलाओं की सक्रिय भूमिका को देखा जा सकता है। महिलाओं ने जागरूकता, शिक्षा एवं कुशलता द्वारा लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना शुरू किया है। समाज में महिला अधिकारों, महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वायत्तता के लिए राज्य एवं नागरिक समाज की गहन और अधिक वास्तविक भागीदारी व समर्थन होना बेहद जरूरी है। समुदायों में महिलाओं ने विशेष रूप से अपने जीवन को संवारा है। इसके अतिरिक्त, राज्यों में प्रशासनिक स्तर पर, न्यायालयों में राजनीतिक पार्टियों में भी महिलाओं के अस्तित्व के सकारात्मक पहलू और एक सुदृढ़ छवि देखने को मिलती है। गैर–सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समुदायों में जहां महिलाएं एक तरफ सुरक्षित हैं वहीं दूसरी तरफ अपनी पसंद के कार्य में संलग्न भी हैं। जो उन्हें आर्थिक मजबूती के साथ उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि महिलाएं आज के समय में पुरुषों के बराबर ही कार्यभार संभाल रही है और परिवार, समुदाय और राज्यों की प्रगति एवं विकास में उनकी भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता।

सुझाव

ग्रामीण समुदाय में स्वयं सहायता समूह' के द्वारा ऐसे संगठनों का निर्माण करना होगा जिससे ग्रामीण और बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। उनके मानसिक स्तर का विकास करने के लिए उनके अन्दर इच्छाशक्ति, जागृति, मनोबल, हौसला आदि उत्पन्न करना आवश्यक है। देश के बड़े–बड़े उद्योगों, संगठनों, क्षेत्रों से जुड़ी किसी भी क्षेत्र की महिलाएं विशेषज्ञ अगर अपना थोड़ा सा समय किसी भी रुप में महिला प्रशिक्षण में देंगी, तो देश की तरक्की की राह आसान हो जाएगी और पुरुषों पर महिलाओं की निर्भरता में भी कमी आएगी। महिलाओं में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास का विकास होगा, जहां महिलाएं निर्णय लेने में स्वतंत्र होंगी। इस प्रकार महिलाएं देश में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी को समझेंगी भी और निभाने के लिए सक्षम भी बनेंगी। जैसेः मणिपुर की सफल महिला उद्यमी सूरबाला ने मुद्रा योजना एवं स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 2017 में दो–दो लाख रुपए लेकर अपना गृह सज्जा का सामान बनाने का व्यवसाय शुरू किया और तीस हजार रुपए प्रति माह कमाती हैं। जमशेद, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर हथकरघा स्वयं सहायता समूह से संबद्ध हैं। इस समूह से 20–25 लोग जुड़े हैं। इनका हाथ से बुनी दरी, कालीन आदि बनाने का काम है। इनके उद्यम से आस–पास के लोगों को रोजगार भी मिल जाता है और स्वयं की भी अच्छी आमदनी हो जाती है।

इस प्रकार स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिसका लाभ उठाकर महिलाऐं सशक्तिकरण की राह में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं, क्योंकि वस्त्र मंत्रालय ने बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करते हुए 35 लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए ई–कॉमर्स पोर्टल बनाया है (कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 2023)।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

कबीर, नैला. 1998. *सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट.* आई डी एस डिस्कशन. पेपर न. 363.

गौतम, एच.आर0, 2023. दिसम्बर. ''गांवों में आर्थिक विकास को बढ़ावा,'' पृष्ठ. 36।

पांडे,मृणाल. 2006. "भारतीय स्त्री प्रजनन और यौन जीवन". राधाकृष्ण पेपर बैक्स, पृष्ठ. 133।

बुआ, सिमोन डी, 2009. द सेकेंड सेक्स, अल्फ्रेड ए. केएनओपीएफ पब्लिकेशन।

रदरफोर्ड, स्टुअर्ट. 1997. द पुअर एंड दियर मनी, ऑक्सफोर्ड इण्डिया पेपरबैक्स।

योजना, दिसम्बर 2024.

दृष्टि, दिसम्बर 2024.

शिवा, वंदना, 1999. कॉलोनियलिज्म एंड द इवोल्यूशन ऑफ मस्कुलिनिस्ट फॉरेस्ट्री पृ0 41.

पाण्डेय, शशि, 2016. ''स्वयं सहायता समूह, लघु ऋण एवं महिला सशक्तीकरण–एक अध्ययन'', इन्ट. जे0 एड. सोशल साइन्स 4(2): अप्रैल–जून पृ0 64–68।

नकवी, हिना 2023. 'समता मूलक समाज का ताना–बाना', कुरुक्षेत्र, दिसंबर।

गुप्ता, रोहित एवं पांडे, आशीष 2024. 'आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (अमूल)' कुरुक्षेत्र, जनवरी।

स्वाइन बाली आर.एफ. वाई. वेलेनटाइन. 2007. डज माइक्रो फाइनेंस एम्पावर वीमेन?एवीडेंस फ्राम सैल्फ हैल्प ग्रुप्स इन इंडिया, ऊपसाला यूनिवर्सिटी।

स्वाइन बाली आर., वर्गीस ए. 2014. *इवैल्यूएअिंग द इंपैक्ट ऑफ ट्रेनिंग इन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया.* यूरोपियन जरनल ऑफ डवलपमेंट रिसर्च, 26, 870–885. https://doi.org/10.1057/ejdr.2014.17

त्रिपाठी, आशुतोष कुमार. 2010. *स्प्रेड ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप – बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया.* जर्नल ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्ट्डीज. 49 (2).

श्रीवास्तव, ए. (2005). *विमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुपः फाइंडिंग्स फ्रॉम ए स्टडी इन फोर स्टेट्स.* सोशल चेंज, 35 (2), 56–72.

श्रीवास्तव, अलका 2006: विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन दी प्रोसेस ऑफ रुरल डवलपमेंट' इन किरन प्रसाद (संपादित) विमेन इन रुरल डवलपमेंट, देहलीः दी वीमेन प्रेस, पृ. 81.99।

हाशमी, एम. सैय्यद. 1996. *सेल्फ हेल्प ग्रुपः ए की स्टोन ऑफ माइक्रोफाइनेंस इन इंडिया वुमन एम्पावरमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी. वर्ल्ड डेवलपमेंट.* वॉल्यूम 24, इश्यू 4, पृष्ठ. 635–653.